'हैदराबाद राज्य की मुक्ति' की 75वीं वर्षगांठ पर सालभर कार्यक्रम आयोजित करेगा केंद्र

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे

नई दिल्ली,एजेंसी।

हैदराबाद 'राज्य की मुक्ति' के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार सालभर कार्यक्रम आयोजित करेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। रेड्डी ने इस संबंध में तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें हैदराबाद परेड मैदान में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया है।

उन्होंने तीन सितंबर को लिखे पत्र में कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने हैदराबाद राज्य मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के आयोजन को मंजूरी दी है। रेड्डी ने तीनों मुख्यमंत्रियों– के. चंद्रशेखर राव (तेलंगाना), बसवराज बोम्मई (कर्नाटक) और एकनाथ शिंदे (महाराष्ट्र) से यह भी अनुरोध किया कि वे अपने राज्यों में उद्घाटन दिवस मनाने के लिए उचित कार्यक्रम आयोजित करें।

उन्होंने लिखा कि तीनों मुख्यमंत्री पूरे साल के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करें और इन योजनाओं को भारत सरकार के साथ साझा करें, ताकि साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाने में समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

हैदराबाद राज्य निजाम शासन के अधीन था और पुलिस ने भारत में इसका विलय कराने के लिए 'ऑपरेशन पोलो' नाम से अभियान चलाया था, जो 17 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ था।

सिकंदराबाद से सांसद रेड्डी ने बाद में ट्वीट किया कि उद्घाटन कार्यक्रम ₹संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में₹ आयोजित किया जाएगा और यहनिजाम तथा रजाकारों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के जीवन और बलिदान को प्रदर्शित करेगा₹। उन्होंने पटेल के साथ अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान की एक अभिलेखीय छवि को साझा करते हुए ट्वीट किया, यह समारोह सरदार वल्लभभाई पटेल और उन सभी लोगों के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगा, जिन्होंने मुक्ति संग्राम के दौरान बलिदान और योगदान दिया।

तीनों मुख्यमंत्रियों को अपने पत्र में उन्होंने यह भी लिखा, जैसा कि आप जानते हैं, जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो 562 रियासतों ने भारतीय संघ में विलय की घोषणा की। तत्कालीन हैदराबाद राज्य की तरफ से इसका विरोध हुआ। 17 सितंबर 1948 को, भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के एक साल से अधिक समय के बाद, तत्कालीन हैदराबाद राज्य, जिसमें पूरा तेलंगाना राज्य और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कुछ जिले शामिल थे, को निजाम के शासन की क्रूरता और अत्याचार से आजादी मिली। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन पोलो' के तहत सरदार पटेल की त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई के कारण यह संभव हुआ।

'हैदराबाद मुक्ति दिवस' के बजाय राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कहा जाए: ओवैसी

हैदराबाद,एजेंसी। ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएमआईएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' के बजाय 'राष्ट्रीय एकता दिवस' नाम से समारोह मनाने की मांग की थी। उन्होंने यह दावा केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर को 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' मनाने की घोषणा करने के महज कुछ घंटों के बाद किया। ओवैसी ने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतकारियों तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन के बलिदानों को याद करते हुए कहा कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले आम हिंदुओं और मुसलमानों ने लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र सरकार के तहत एकीकृत भारत की वकालत की थी। उन्होंने कहा, यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि विभिन्न रजवाड़ों का विलय निरंकुश शासकों से क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने भर नहीं था। सबसे अहम बात है कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इन क्षेत्रों के लोगों को स्वतंत्र भारत के अभिन्न अंग के तौर पर देखा। इसलिए केवल मुक्ति शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय ' राष्ट्रीय एकीकरण दिवस' अधिक उचित होगा।

एक नजर

मेघालय के पूर्व पुलिस अधिकारी भाजपा में शामिल

शिलांग,एजेंसी। मेघालय–असम कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी मरिहोम खारकांग शनिवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महासचिव (संगठन) बीएल संतोष की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। खारकांग ने 2023 में उत्तरी शिलांग विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लडने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। केन्द्रीय मंत्री श्री मेघवाल, मेघालय के कैबिनेट मंत्री सनबोर शुलाई, श्री बी.एल. संतोष आदि नेताओं ने श्री खारकांग का भाजपा में स्वागत किया।

केरल में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे अमित शाह

तिरुवनंतपुरम,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को तिरुवनंतपुरम में दक्षिण भारतीय राज्यों और केंद्र–शासित प्रदेशों की दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। शाह के अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, अन्य दक्षिणी राज्यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) के मुख्यमंत्री तथा मंत्री और दक्षिण भारत के केंद्र–शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) के उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल होंगे। केरल में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दों और साझा हितों के मामलों पर चर्चा होगी।

अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए केंद्र कदम उठाए: विजयन

तिरुवनंतपुरम,एजेंसी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार से शनिवार को आग्रह किया कि वह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राज्यों को लाभदायक तरीके से खर्च करने में सक्षम बनाए। विजयन ने क्षेत्रीय परिषद की यहां 30वीं बैठक में कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की अनुवर्ती सूची के आधार पर प्रस्तावित कानूनों को लागू करने से पहले उन पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। विजयन ने कहा, मतभेद हो सकते हैं लेकिन चर्चा और बहस के जरिए मतभेद के इन क्षेत्रों को कम करके सर्वसम्मति बनाई जा सकती है।

लद्दाख में अंधेरे गगनमंडल की सफारी सुविधा तीन माह में: सिंह

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रात्रिकाल में गगन–मंडल के दृश्यों का दर्शन कराने वाली भारत की पहली 'नाइट स्काई सेंचुरी' लद्दाख के हनले इलाके में तीन माह में तैयार कर ली जाएगी। वहां प्रकाश प्रदूषण पर अनुसंधान और अध्ययन भी किए जाएंगे।

डॉ. सिंह ने लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के.माथुर के साथ राजधानी में एक बैठक में इस केंद्र शासित क्षेत्र की परियोजनाओं के विषय में वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। इस नाइट स्काई संेचुरी में विभिन्न तकनीकों वाली दूरबीने लगायी जाएंगी जिनमें ऑप्टिकल, इन्फ्रा–रेड और गामा–रे टेलीस्कोप शामिल होंगी। लद्दाख का हनले इस तरह की सुविधा वाला दुनिया के

सबसे ऊंचे स्थानों पर स्थापित रात्रि गगनमंडल दर्शन अभयारण्य होगा। डॉ. सिंह ने कहा है कि प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हनले में तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा । इससे भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

शनिवार को जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री माथुर ने डॉ सिंह से चमड़ा केंद्र, लेह बेरी, शिक्षा मेला और सीएसआईआर समर्थित योजनाओं पर परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। बयान के मुताबिक केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), चेन्नई के वैज्ञानिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सीएलआरआई की एक क्षेत्रीय शाखा स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए इस साल के अंत तक लद्दाख का दौरा करेगा। सिंह ने कहा कि उस क्षेत्र में जानवरों की व्यापक विविधता को देखते हुए ऐसे केंद्र का वहां होना महत्वपूर्ण होगा।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने एक अनूठी और अपनी तरह की पहली पहल में लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई संेचुरी स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। यल हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित होगा। यह भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा। डॉ. सिंह के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी औरपृथ्वी विज्ञान का प्रभार है।

उन्होंने बताया कि डार्क स्पेस (रात्रि आकाश) अनुसंधान शुरू करने के लिए हाल ही में लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) लेह और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ने कहा कि सभी हितधारक संयुक्त रूप से अवांछित प्रकाश प्रदूषण और रोशनी से रात के आकाश के संरक्षण की दिशा में काम करेंगे, जो कि वैज्ञानिक अवलोकन और प्राकृतिक आकाश की स्थिति के लिए एक गंभीर खतरा है।

अजीत डोभाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल से मुलाकात की

मुंबई, एजेंसी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से यहां उनके आवासों पर मुलाकात की। राज्यपाल के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि डोभाल ने राजभवन में कोश्यारी से मुलाकात की और यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने शिंदे से मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 'वर्षा' में मुलाकात की और वहां भगवान गणेश के दर्शन किए। शिंदे के कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया कि डोभाल ने मुख्यमंत्री आवास पर भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा–अर्चना की।

ब्रिटिश काल के कर्नाक पुल को गिराने का काम शुरू

मुंबई, एजेंसी।

दक्षिण मुंबई में सीएसएमटी और मस्जिद स्टेशन के बीच स्थित ब्रिटिश काल के कर्नाक पुल को गिराने का काम शुरू हो गया है और मध्य रेलवे के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि इसे पूरी तरह से ढहाने के काम में करीब तीन महीने लग सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि पुल 1866–67 में बनाया गया था और 2018 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई की एक विशेषज्ञ टीम ने इसे असुरक्षित घोषित कर दिया था, हालांकि इस पर भारी वाहनों की आवाजाही 2014 में ही रोक दी गई थी।

मध्य रेलवे के अधिकारी ने कहा कि सीमेंट की ऊपरी परत को हटाने का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, चूंकि पुल उन पटरियों के ऊपर बना है जिन पर भारी उपनगरीय ट्रेन यातायात दिखाई देता है, हम रात के दौरान ढहाने–गिराने का काम करेंगे। हम रविवार को नियमित रखरखाव के लिए होने वाले मेगा ब्लॉक (जिस अवधि में ट्रेन की आवाजाही रुकी होती है) के दौरान भी काम करेंगे।

अधिकारी ने कहा कि गर्डर को हटाने, पुल गिराने के काम को पूरा करने और क्रेन की मदद से स्टील के ढांचे को हटाने के लिए 30 घंटे के 'मेगा ब्लॉक' की भी योजना है। मध्य रेलवे के अधिकारी ने कहा कि पुल को गिराने में तीन महीने का समय लगने की संभावना है।

पुडुचेरी ने 2200 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मांगी

पुडुचेरी,एजेंसी।

पुडुचेरी ने केंद्र शासित प्रदेश में हवाई अड्डे के विस्तार सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 2,200 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मांगी है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की शनिवार को आयोजित बैठक में अपने भाषण में, हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पड़ोसी तमिलनाडु से भूमि के लिए केंद्र शासित प्रदेश की मांग दोहरायी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि पुडुचेरी सरकार खुश है कि केंद्र ने एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता' योजना शुरू की है। उन्होंने कहा, इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करनी हैं। हालांकि, वह केंद्र से मुआवजा समर्थन और केंद्रीय बजट का हिस्सा नहीं है जैसा कि अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं।

मुरुग मठ के मुख्य पुजारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

बेंगलुरु,एजेंसी। बेंगलुरु की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केंगेरी होबली में संपत्ति से संबंधित एक मामले में मुरुग मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुग शरनारू के विरुद्ध गैर जमानती वारंट फिर जारी करने का आदेश दिया है।

उधर, इस मशहूर पत्रकार और रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित पी साईनाथ ने शुक्रवार को कहा कि वह बसवश्री पुरस्कार वापस कर रहे हैं, जो उन्हें 2017 में मुरुग मठ द्वारा प्रदान किया गया था। ताजा विवाद सुलिकेरे गांव में सात एकड़ संपत्ति से जुड़ा है।

यह जमीन जिस कीमत पर कथित रूप से बेची गयी थी, वह बाजार मूल्य से बहुम कम थी।

संस्थानों को भविष्योन्मुखी बनायें, चुनौतियों से निपटने में आईआईटी से काफी अपेक्षा: द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली,एजेंसी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी की गाथा को स्वतंत्रत भारत की कहानी बताते हुए शनिवार को कहा कि आने वाले समय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म ईंधन, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में योगदान की अपेक्षा हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, आईआईटी राष्ट्र का गौरव रहे हैं और उनकी कहानी स्वतंत्र भारत की कहानी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास प्रतिभाओं का बड़ा भंडार हैं जिनका पूर्ण रूप से

अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इस दिशा में आईआईटी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुर्मू ने कहा कि आईआईटी, दिल्ली ने समाज से जुड़े मुद्दों के प्रति हमेशा अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखायी है और कोविड–19 महामारी के प्रथम चरण में संस्थान द्वारा रैपिड एंटीजेन किट, फेस मास्क आदि विकसित किया गया था। उन्होंने कि महामारी के दौरान आईआईटी, दिल्ली का योगदान इस बात का उदाहरण है कि स्वास्थ सुरक्षा के विषय में अकादमिक संस्थान किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश की जनसंख्या अधिक होने के मद्देनजर भविष्य के लिए नीतियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि तभी आबादी का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा, हमें अपने संस्थानों को नये तरह के अध्ययन के ढांचे, व्यवस्था एवं पाठ्य सामग्रियों से लैस करने की जरूरत है ताकि इन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।

मुर्मू ने कहा कि आईआईटी, दिल्ली बड़े पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार में योगदान दे रहा है।

उन्होंने कहा, जब हम वर्ष 2047 का उल्लेख करते हैं तब जलवायु परिवर्तन हमारे समक्ष गंभीर चुनौती बन कर आ रहा है और एक विकासशील देश होने के नाते हमारे अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने जीवाश्म ईंधन का जिक्र करते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिये आईआईटी से काफी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की बेहतर होती स्थिति में आईआईटी का बड़ा योगदान है।

शिवसेना ने स्मार्ट मीटर के विरोध में किया प्रदर्शन

जम्मू, मेट्रो मीडिया।

शिवसेना जम्मू कश्मीर ईकाई ने महंगाई, बेरोजगारी और मंदी के दौर में सरकार द्वारा जनता की जेबे पूरी तरह खाली करने के इरादे से लगाए गए बिजली के स्मार्ट मीटरों को सबसे बड़ा लुटेरा बताते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तथा ₹निःशुल्क बिजली पानी हमारा हक₹ का नारा दिया ।

पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीश साहनी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने प्रैस क्लब के बाहर स्मार्ट मीटर को सबसे बड़ा लुटेरा बताते हुए पुतला फूंका और जनता की जेब पर डाका डालने वाले इन लुटेरों को उखाड़ फैंकने की अपील की।

साहनी ने कहा जिस प्रदेश में अपार जल संसाधन तथा बिजली परियोजनाओं का भंडार हो और जहां

18–20 हजार मैगावाट के पैदावार की संभावनाएं हो वहां जनता को 24 धंटे, निःशुल्क बिजली दिया जाना उनका हक बनता है।

मगर सरकार का मकसद राहत देना नहीं, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना बन चुका है।

इसी कारण बिजली बिलों में लगातार बढ़ौतरी और तेज रफ्तार के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे है। साहनी ने कहा कि स्मार्ट मीटर और मोटी मोटी तारे, जनता के राहत के लिए नहीं बल्कि निजी कंपनियों को लुभाने और फायदा पहुंचाने की तरफ बढ़ते कदम है।

साहनी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और मंदी के इस दौर में जनता को राहत सरकार का फर्ज है मगर तेज रफ्तार से चलने वाले स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों के कई गुणा बढ़ने से आम लोगों की नींद हराम हो चुकी है।

साहनी ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों की लूट और इन्हें निजी हाथों में सौंपने के मनसूबे कतई कामयाब नहीं होने देंगे । इसके लिए एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। साहनी ने तेजी से चलने वाले मीटरों की गहन जांच के साथ सरकार से निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के मिशन से बाहर निकल जानता को राहत पहुंचाने की नसीहत दी।

इस मौके पर महासचिव विकास बख्शी, चेयरमैन राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष संदीप भगत,अध्यक्ष कामगार विंग राज सिंह,अध्यक्ष युवा विंग बिन्नी महाजन, शशिपाल, अशोक कुमार, नरेश कुमार,संजीव सूदन , सुरेन्द्र कुमार समेत कई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

भाजपा विधायक ने महिला को झिड़का

बेंगलुरु,एजेंसी। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक अरविंद लिम्बावली ने कथित तौर पर शहर में एक जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सवाल पूछने और अर्जी देने की कोशिश कर रही एक महिला को झिड़क दिया।

इस कथित घटना का वीडियो वायरल हो गया है। विपक्षी कांग्रेस ने वीडियो क्लिप को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कर्नाटक की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार ने शनिवार को लिम्बावली के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि वह विधायक के लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को राज्य की सत्ता में नहीं रहना चाहिए।

मांडविया ने अंगदान को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अंगदान को लोकप्रिय बनाने के लिए 'जनभागीदारी' पर जोर देते हुए कहा है कि अंग दान का मुद्दा हमारी आम सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है।

मांडविया ने शनिवार को यहां 'स्वस्थ सबल भारत' सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह

हमारी सांस्कृतिक परंपरा में है कि हम न केवल अपने बल्कि दूसरों के लाभ के बारे में सोचते हैं और अंग दान का मुद्दा इस तरह की दृष्टि से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।

Morning Glory Leasing & Finance Limited
Regd. Off: Iris House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi- 110046
CIN: L67120DL1984PLC018872, Tel. No.: +91 11 47119100
Email:morninggloryleasing@gmail.com, Website: www.morninggloryleasing.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Morning Glory Leasing and Finance Limited will be held on Friday, the 30th day of September, 2022 at 11:00A.M. at its registered office atIRIS House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi – 110046.

Notice is further given that pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the shareholders attending the AGM.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 23rd September, 2022 (i.e. Cut-off date) may cast their vote electronically on the Businesses as set out in the Notice of the 38th AGM through Remote E-voting services provided by National Securities Depository Ltd ('NSDL'). All the members are informed that:

a) Notice of 38th AGM along with Annual Report for the FY 2021-22 has been sent to all the members in Physical form on their registered address through permissible mode.
b) The remote e-voting shall commence on 27th September, 2022 (09.00 a.m. IST) and end on 29th September, 2022 (05.00 p.m. IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond 29th September, 2022 (05.00 p.m. IST).
c) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or bssdelhi@bigshareonline.com.
d) The facility for voting through Ballot Paper/Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot paper/Polling Paper.
e) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Ballot paper/Polling Paper.
g) The Notice of 38th AGM is available on the Company's website www.morninggloryleasing.in and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com.
h) In case of any queries members may contact the undersigned at +91 11 47119100 and may also write to the undersigned at morninggloryleasing@gmail.com or at the Registered office address at IRIS House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi- 110046.

For Morning Glory Leasing & Finance Limited
Sd/-
Payal Madaan
Company Secretary cum Compliance Officer

Date: 03.09.2022
Place: New Delhi

कृषि खेतों को पानी आपूर्ति के लिए बनी रणवीर नहर मे लगी पानी की पाइपें भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त

मशहूर आरएसपुरा की बासमती चावल फसल पर बना बड़ा संकट

कुमार सतीश

जम्मू। भारत पाक सीमा से सटे आरएसपुरा इलाके की बासमती फसल पर भारी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिसकी वजह बासमती फसल के लिए रणबीर नहर से मिलने वाला पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी अहम वजह पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण रणबीर नहर में लगी बेहद पुरानी पानी की पाइपों के स्थानीय धड़प इलाके में क्षतिग्रस्त हो जाने से रणबीर नहर के पानी की आपूर्ति आगे किसानों को खेतों तक ना पहुंच पाने के कारण बासमती की फसल लगातार बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिससे आरएसपुरा तथा बिश्नाह

इलाके की किसान खासी प्रभावित हुए हैं।

बताया गया कि समूचे जम्मू जिले में करीबन 45हजार हेक्टेयर भूमि पर यह फसल पैदा होती है जिसमें अकेले आर एस पुरा क्षेत्र में करीब 22 हजार हेक्टेयर भूमि पर बासमती पैदा होती है। यहां के किसानों पर बनी इस बड़ी आपदा को लेकर डोगरा सदर सभा के प्रमुख ठाकुर गुलचैन सिंह चाढक में भी पुरजोर आवाज उठाई है। चाढक के मुताबिक डोगरा महाराजा द्वारा बनाई गई इस रणबीर नहर में ग्लेशियर का पानी आता है, जिसकी वजह से आएसपुरा की बासमती सुगंधदायक एवं मशहूर हुई है। आज इसकी फसल पर भारी संकट आन पड़ा है।

उन्होंने कहा कि इस नहर के धंसने के बाद यंहा के हालात का जायजा लेने के लिए राज्य प्रशासन के सलाहकार तथा दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर आए थे ।लेकिन कोई भी समाधान ना होने के कारण किसानों की समस्या अभी तक लगातार बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर ऑल इंडिया किसान सभा के प्रधान किशोर कुमार शर्मा ने उप राज्यपाल शासन से किसान और किसानी को बचाने के लिए त्वरित पर्याप्त कार्रवाई करने की मांग की है ताकि इलाके के किसानों कि बासमती की फसल यूं ही बर्बाद ना हो जाए। जबकि यहां के किसान पहले से ही जारी लंपी पशु रोग के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि दडप के पास रणबीर नहर में लगी बरसों बरस पुरानी करीब 100 मीटर पानी की पाइप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आगे खेतों में पानी की आपूर्ति ना होने से करीब 30हजार किसान प्रभावित हो रहे हैं।

शर्मा के संगठन की ओर से पिछले दिनों अपनी इन मांगों को लेकर एक प्रदर्शन भी किया गया था। इसमें राज्य तथा जिला प्रशासन ध्यान केंद्रित करते हुए इस समस्या का जल्द से जल्द निदान करने की मांग की गई थी। बताया गया कि इसी मुद्दे को लेकर सुचेतगढ़ से जिला विकास परिषद के सदस्य बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीते तरनजीत सिंह टोनी ने भी महकमें के चीफ इंजीनियर से बातचीत कर क्षतिग्रस्त रणबीर नहर को जल्द से जल्द ठीक करवाकर खेतों में बुवाई गई बासमती फसल को बचाने व किसानों को राहत पहुंचाने की मांग की ।